MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Essential Commodities (Amendment) Bill, 1976

SECRETARY-GENERAL : Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of Rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that the Lok Sabha at its sitting held on the 26th August, 1976, agreed, without any amendment, to the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1976, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 11th August, 1976."

RESOLUTION RE: ENSURING REMUNERATIVE PRICES FOR AGRICULTURAL PRODUCE AND MAINTAINING PARITY IN PRICES BETWEEN AGRICULTURAL PRODUCE AND INDUSTRIAL GOODS

—contd.

श्री रणवीर सिंह (हरियाणा): सभापतिजी,

[Mr. Deputy Chairman in the Chair.]

श्री इन्द्रदीप सिंह ने देश का ध्यान इस बात की तरफ दिलाया कि खत के अन्दर जो पैदावार होती है उसकी सही कीमत मिले और इसके साथ-साथ जो कारखानों के अंदर चीजें पैदा होती हैं उनकी कीमतों में संतुलन होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। यह क्यों जरूरी है उसका कारण मैं आगे चल कर बताऊंगा। इससे पहले कि मैं और कुछ कहूं मैं सदन का ध्यान इस बात की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जो चीजे खेती की पैदावार करने में लगती हैं उनकी कीमतों में कहां तक फर्क आ गया है। इस बात की तरफ ध्यान दिलाने से पहले मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा वह यह कि यह देश कृषि प्रधान देश है। इस देश के अंदर 70 परसेंट भाई खेती का धंधा करते हैं, खेती पर निर्भर रहते हैं। हमारे इंडैक्स नंबर हैं। जो 30 फीसदी भाई हैं उनके साथ न्याय हो इसके लिए कंजूमर इंडैक्स नंबर हैं लेकिन जो 70 फीसदी हैं, जो खेती का धंधा करते हैं उनके साथ न्याय नहीं हो सकता प्रजातंत्र के अंदर उनके लिए कोई इंडैक्स नंबर नही हैं। उनके लिए इस बात की कोई जानकारी नही है कि पहले कितना खर्चा होता था और अब कितना खर्चा होता है इसके लिए खेती के लिए जो चीजें चाहिएं उनके लिए खर्च इत्यादि के आंकड़े देखने चाहिएं। मै, सरकार ने जो आंकड़े कृषि मंत्रालय की कंसलटेटिव कमेटी में दिए हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि यह मशीन युग है और यह इसलिए कि खेती में जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है वह मेहनत कम हो। मैं आपका ध्यान और बातों की तरफ न ले जाकर ट्रैक्टरों की कीमतों की तरफ ले जाना चाहता हूं। उपसभापति जी, 3-4 मोडल के ट्रैक्टर जो है उनकी कीमतों में कितना फर्क आया है यह मै बताना चाहता हूं। एम० एफ० 1035 होर्सपावर के ट्रैक्टर की कीमत 1-2-70 को 21 हज़ार 1-40 रुपये थी।

30-6-66 को उसकी कीमत 43274.90 रु० हो गई। इन्टरनेशनल बी-275 जो 35 हार्स पावर का है, उसकी कीमत 1-2-70 को 19,570 रु० थी, लेकिन 30-6-76 को उसकी कीमत 43750 रु० हो गई। एस्कोर्ट ट्रैक्टर जो 35 हार्स पावर का होता है उसकी कीमत 1-2-70 को 17,910 रु० थी। अब उसकी कीमत 36,528 रु० हो गई है। इसी तरह से दूसरा ट्रैक्टर जो 25 हार्स पावर का होता है, उसकी कीमत पहले 14,500 रु० थी। लेकिन अब उसकी कीमत 35,910 रु० हो गयी है। इसी तरह से फोर्ड 3600, पहले 35,595 रु० का था, लेकिन अब उसकी कीमत 56,168.80 रु० हो गई है। हमारी सरकार की कोशिश है कि चीजों की कीमतें न बढ़ने पायें। लेकिन फोर्ड ट्रैक्टर की कीमत तीन चार महीनों में ही पांच हज़ार रुपये बढ़ गई है। इसी तरह से दूसरे ट्रैक्टरों

[श्री रणबीर सिंह]

में भी तीन हजार से लेकर पांच हजार रुपयों की वृद्धि हुई है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि हमने ट्रैक्टरों पर से एक्साइज ड्यूटी घटा दी है और दूसरी तरफ ट्रैक्टरों के टायरो की कीमतें बढ़ती जाती हैं। आप जानते है कि आधुनिक युग में हमारे देश में ट्रैक्टरों से खेती होने लगी है और ट्रैक्टर ही अनाज पैदा करते हैं। ऐसी हालत में हमारे देश के कारखानेदार ट्रैक्टरों की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं और हमारा कृषि मंत्रालय संतोष से बैठा रहे, यह बात समझ में नहीं आती है। यह बात भी समझ मे नही आती है कि हमारी सरकार इस दिशा में कुछ कर सकती है या नही ? मै चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। हमारे कृषि मत्रालय में जब बाबू जगजीवन राम जी 1967-68 में आए तो उस वक्त यह नीति निर्धारित की गई थी कि ट्रैक्टरों के ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नही लगाई जाएगी और विदेशों से आये ट्रैक्टरो के ऊपर कोई कस्टम नही होगा। लेकिन इन नीतियों के छोड़ देने से ट्रैक्टरों की कीमतों में वृद्धि होती रही है।

उपसभापति जी, एक तरफ तो इस प्रकार की हालत है और दूसरी तरफ कार की कीमतों में कमी की गई है। कार के बिना हमारे देश का काम नहीं चल सकता है, लेकिन ट्रैक्टर, जिसके जरिए किसान खेती की पैदावार बढ़ाता है, उसकी कीमतें बढ़ाई जाती हैं। मै आपके सामने कुछ और भी आंकड़े रखना चाहता हूं। हमारे देश को आजादी के बाद विदेशों से कितना अनाज खरीदना पड़ा, यह इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी अनाज के मामले में विदेशों पर निर्भर रहे, यह किसी भी दृष्टि से उचित नही है। हमारा देश करोड़ों रुपये विदेशों को दे चुका है। इस सबंध में मेरे पास जो आंकड़े हैं वे सन् 1974 तक के है। अब तक हम ने विदेशों से जो अनाज और दालें आदि मंगाये हैं उस पर हम 8,939 करोड 70 लाख रुपये खर्च कर चुके है। ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं ये सन् 1954 से 1974 तक के हैं। सन् 1946 से 1954 तक विदेशी मुद्रा के रूप में जो धनराशि हम विदेशो को दे चुके हैं वह 1036 करोड़ 83 लाख रुपये की है। इन दोनों को मिलाकर 9,976 करोड़ 53 लाख रुपये हम विदेशो को दे चुके हैं। इस प्रकार से सन् 1946 से 1974 तक इतनी बड़ी धनराशि अनाज के बदले में हम बाहर के देशों को दे चुके हैं। मैं समझता हूं कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

श्री उपसभापति : श्री रणबीर सिंह जी, नियमों के अनुसार आप 15 मिनट बोल चुके हैं। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रणबीर सिंह : उपसभापति जी, अकेले कपास के ऊपर जो बाहर से आई, उसके ऊपर जो खर्च किया गया उसके 1972 तक के आंकड़े मेरे पास है। हमने 1616 करोड़ 78 लाख रुपये कपास बाहर से मंगाने पर खर्च किये। तो इस तरह से हमने 11594 करोड़ रुपये की चीजें विदेशों से खरीदी है जिसमें खेती के अतिरिक्त और चीजें शामिल नहीं हैं। यह क्यों हुआ ? क्या देश के अन्दर इन चीजों को पैदा करने की शक्ति नहीं है ? इस देश के अन्दर पैदा करने की शक्ति है। हमने खेतों में पानी की, सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिये 35 सौ करोड़ रुपये खर्च किये और उसके ऊपर भी आज हालत यह है कि प्लानिंग कमीशन के डा० मोनहास ने कहा कि एक फीसदी सूद भी दे दें तो भी कुछ काम चल सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह विदेशी अनाज, जो बाहर से आया है, जो खाने की चीज है उसके ऊपर कितना सूद आप देते है। यह सूदखोरी की नीति क्या हमारे लिये बनी है ? मैं यह मानता हूं कि यह जो नीति हमारी है, जिस नीति के मुता-

बिक यह सरकार चल रही है वह एक तरह से बणिये की नीति हो गयी है । सरकार की यह नीति जो हो गयी है उससे हमें ऐतराज है । पहले किसान साहूकारों से ज्यादा ब्याज पर रुपये लेते थे लेकिन आज सरकार द्वारा किसानों को 17 और 18 परसेन्ट सूद पर रुपया दिया जा रहा है और इसका फल यह होता है कि किसान सरकार को वह ब्याज अदा नही कर सकता है । तो हमारा यह जो देश है, इस देश के जो आम आदमी है, उनसे ब्याज रुपया लेने के लिये ही क्या हमारी आर्थिक नीति रहेगी, ब्याज हेर-फेर में लेंगे ।

देश के जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट है, जिनकी सफलता के बारे मे पहले कोई कुछ नही कह सकता, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर, कागजात सिक्योरिटी के ऊपर रिजर्व बैक रुपया ब. है लेकिन वह, जिस चीज की गारंटी है उसके ऊपर रुपया नही बांटता है । इस देश की तरक्की में यह आर्थिक विज्ञान जानने वालों की बात है । यदि हमे इस देश के अन्दर एक समाजवादी ढांचा बनाना है, तो हमारा आर्थिक सोच अभी वही कैपिटिलिस्ट ढंग है, मरकन्टायल इकानामी है, तो उसको जब तक हम नही बदलेंगे उस वक्त तक इन किसानों के साथ न्याय नहीं होगा, न ही देश के साथ न्याय होगा । किसान के हित में तरक्की होनी चाहिए लेकिन मैं कहता हूं कि ....

[*Time bell rings*]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now I will call the next Speaker.

श्री रणबीर सिंह : यदि किसान सुखी होगा तो देश अपने पैरों पर अपने आप खड़ा हो जायेगा । इसलिये आप आर्थिक नीति के अन्दर तब्दीली करिये । कार के बजाय ट्रैक्टर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी घटाइये, खेती मे काम आने वाली चीजों पर एक्साइज ड्यूटी घटाइये ।

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, our comrade Indradeep Sinha has brought before the House such a Resolution which is totally consistent with the spirit of emergency, the spirit of 20-point programme. I think this is the most psychologically favourable hour when the emergency and the 20-point programme attracted the attention of the country and turned it towards the poorer sections, specially the rural poor. Sir, in this situation when we are getting the overall support, psychological co-operation and physical co-operation from so many forums and so many organisations, when so many organisations and the mass media are propagating for the amelioration of the poorer sections, I would ask the hon. Minister to help the situation by supporting and accepting the Resolution.

Sir, we are living in a mixed economy, though monopolised by some petty groups with the connivance of the multi-national corporations. So, our emergency spirit says that our first enemy should be the monopolies and the multi-national corporations. Keeping that in view our strategy and our programme should be to ameliorate the conditions of poorer sections especially of weaker sections in the villages by making agricultural prices remunerative so that agricultural production is increased. In the meantime, parity between agricultural prices and prices of industrially manufactured products should be maintained so that we have a balanced economy for the future growth of our country. In this regard, I may point out that in spite of so many fiscal measures and budgetary provisions the Government has failed to stabilise the prices of agricultural commodities and maintain parity in the prices of agricultural commodities and manufactured products.

Sir, if we really want to control the economy of our country in favour of the poorer sections, I think, first of all, we should, as the Resolution points out, control the monopolists. Our target and enemy should be that section. So our first attack will be on monopolists in India and other multi-national corporations. In this connection I would like to draw the attention to some reports appearing in our paper, *the New Age*. It says that Colgate-Palmolive, a multi-national corporation earned 5551 per cent profit. Details I shall not give. Papers says everything. It says that Hindustan Lever made super-profits by fleecing consumers. On the other hand, I see that as a result of all these factors already enumerated above, the prices of Lever products went up by 10 per cent in the case of each piece of Sunlight, Lifebuoy, Rin, Lux, etc. Again, I see that Philips in 1973 made a profit of Rs. 923 lakhs. In 1974 they earned Rs. 1,069 lakh as profits and in 1975 they earned a profit of Rs. 1660 lakhs. Their profits are growing. On the other hand, what do we see in the agricultural sector? We find that jute growers are not even getting the actual cost of production. We find that wheat growers are not even getting the actual cost of production. We find that cotton producers, when there is a

[Shri Sanat Kumar Raha]

glut in the market, are to make distress sales. These are the commodities which fetch international currency in foreign markets, *i.e.*, foreign exchange for our country. What is our national policy then? If these multi-national and national corporations monopolise our economy, is it not the task of the Government to attack them so that they do not monopolise our economy and de-stabilise our economy so that we maintain price stability in our country? In this connection, I may highlight that the Agricultural Prices Commission has fixed the price of raw jute at Rs. 135 per quintal in spite of the fact that the West Bengal Government had made a suggestion that the price at which the commodity should be sold should be Rs. 180 per quintal. The other day I asked the Minister and he started giving explanations. What is cost of production? How can we calculate taking all the factors into consideration? There is rise of price in fertilisers. There is rise of price in pesticides. There is rise of price in all sorts of inputs needed for agricultural production. Taking all these factors and also the minimum wages required to be paid to agricultural labourers into consideration, I think in my district Murshidabad in West Bengal, Rs. 400 are to be spent per bigha of jute cultivation and in 24 Parganas the cost comes to about Rs. 450 per bigha of jute cultivation. If this be so, it is our calculation that Rs. 80 is spent for producing a maund of jute whereas the jute grower is getting only Rs. 54 per maund as per the recommendations of the Agricultural Prices Commission. Is this Just? Similarly, there are reports in the papers about the glut in cloth trade, glut in potatoes and glut in all these things. Why is it so? It is because on the one hand you have already frozen the buying capacity of the workers' community and on the other, the workers and the growers are not getting incentive price. Lots of people are losing their purchasing capacity. In that situation, how can you avoid a glut in the markets? Still, there are manipulations, market manipulations, speculative manipulations on the part of the traders, monopolists and the hoarders. They are the enemies of the country and these anti-social and anti-national sections of the community should be immediately brought before the public so that we can go forward step by step in spite of the mixed economy. When we are proceeding with the ultimate aim and goal of bringing about socialism, of making our country a welfare State where there will be no exploitation, I think we have to make this situation favourable to the poorer sections so that they also have a share in the society. I would request the hon. Minister to take suitable steps to see that these eighty per cent of the people of our country could come up in life and could join the mainstream of our national life and only then can we fight the monopolists and the multi-nationals.

Another item I want to highlight is the short-term and the long-term investment. The National Commission on Agriculture suggested a loan of Rs. 9,000 crores by the end of the Fifth Plan. If that is the amount of investment, how can we solve the problems of the poorer sections of the agriculturists who are resorting to distress sale of their commodities? I want to know from the hon. Minister whether all the credit requirements of these poorer sections have been taken into consideration and whether at least forty per cent of the peasants who have to resort to distress sale, could be covered by this agricultural loan. Otherwise, this investment, I am afraid, will be a futile exercise and there will continue to be exploitation, by the rich, of the poorer sections of the people both in the rural and urban areas. In these circumstances, the calculations of the Agricultural Prices Commission and the credit calculations for agriculture should be taken into account so that the 78 per cent or the 80 per cent of the population can improve its living gradually to make the 20-point economic programme a real success. I am afraid, these piecemeal legislations will not help.

Sir, there are agro-service centres. So many agro-service centres have been opened for the employment of young people but they are not getting any incentive from the banks or from the Government. The banks prefer to assist private traders who can afford to give some money as bribe. If we want to develop our agriculture, the Agriculture Minister should consult the Minister of Finance so that by some arrangement, these agro-service centres could give every help to the needy agriculturists for promotion of agriculture in the country. The last point I would like to suggest is this. When the time is favourable, when it is psychologically favourable and when we have a sufficient buffer stock of foodgrains, why should not the hon. Minister think of taking over the wholesale trade in foodgrains either this year or next year when the Kharif crop would come into the market? This should be done immediately without any delay. During the Emergency period, no progressive measures can be thwarted by the vested interests.

Secondly, Sir, the jute industry is in a chaotic condition. It is going the Indigo way. Vanaspati, tea, jute, textiles and sugar industries should be nationalised. These industries should be taken over by the Government. As a policy and as a principle, these industries should be brought under the State sector. With these words, I conclude my speech.

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम श्री इंद्रदीप सिंह जी को धन्यवाद देना

चाहता हूं जिन्होंने किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दाम और बड़े बड़े पूंजीपतियों के कारखानों में पैदा होने वाली चीजों के दाम के संबंध में चर्चा का विषय उठाया है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1971 से गांव के किसानों की हालत और शहरों की हालत के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। 1971 में हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में एक चुनाव लड़ा गया जिस का उद्देश्य था 'गरीबी हटाओ'। हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों में हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत जनता रहती है और इस में भी कोई दो रायें नहीं हैं कि हिन्दुस्तान जैसे महान देश ने अपने महान नेता के नेतृत्व में महान तरक्की की है और हिन्दुस्तान एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में एशिया और अफ्रीका के बीच आया है। लेकिन इस के साथ साथ आप का ध्यान इस बात पर जरूर दिलाना चाहूंगा कि यदि सही नीतियों का पालन नहीं किया गया तो गांवों के किसान और गरीब होंगे और मोनोपोली कैपिटल और कैपिटलिस्ट्स हिन्दुस्तान में और बढ़ेंगे। 1971 के बाद हमारे देश की स्थिति में क्या फर्क आया है। किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों और किसानों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के दामों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है इस को देखा जाय। यदि 25 हजार रुपये में 1971 में एक ट्रैक्टर मिलता था तो आज वह 50 हजार रुपये का है। यदि 7 रुपये प्रति हार्स पावर बिजली का दाम था 1971 में तो आज बिजली किसान को 15 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से मिलती है। उस समय यदि एक हजार रुपये प्रति जोड़ी बैल मिलता था तो आज उस का दाम तीन हजार रुपये है। लोहे की चीजें जो किसान इस्तेमाल करते थे जैसे फावड़ा, कुदाल, खुरपी का दाम भी आज बढ़ा है। यदि उस का घर गिर गया तो ईंट भी जो 50 रुपये प्रति हजार थी वह आज 115 रुपये हजार में मिलती है। गारे का दाम भी बढ़ा है और सीमेंट का दाम जो 12 रुपये प्रति बोरी था वह आज 24 रुपये प्रति बोरी हो गया है। इसी प्रकार चाहे सीमेंट हो या लोहा हो या कोयला हो या ईंटा हो, बैल हो या खुरपी या खुरपा हो, या किसानों के खेतों में इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैक्टर हो या बिजली हो या फर्टिलाइजर हो, सब का दाम आज बढ़ा है। फर्टिलाइजर जो 50 रुपये बोरी मिलता था 1971 में, वह आज बढ़ कर 105 रुपये बोरी हो गया है। तो किसान के खेतों में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम दुगुने, तिगुने बढ़ गये। इस के बाद जो चीजें किसान अपने व्यक्तिगत जीवन के लिये इस्तेमाल करता है चाहे वह कपड़ा हो या नून, तेल, धनिया इस्तेमाल करता हो, या साबुन इस्तेमाल करता हो या किरोसिन का इस्तेमाल करता हो, जो भी चीजें बाजार में वह खरीदता है और जिन का वह अपने निजी जीवन के लिये इस्तेमाल करता है उन सब के दाम दुगने और तिगुने हुए हैं और जिन चीजों से खेतों की पैदावार बढ़ती है उन के दाम भी बढ़े हैं। आदरणीय उपसभापति महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हम ने मिनिमम वेजेज भी 5 रुपये तय किये हैं। यदि किसान को मिनिमम वेजेज का कानून गांवों में पालन करना पड़े तो मैं समझता हूं कि वह किसान तो अपना खेत भी बंधक रख कर भाग जायगा। अभी कल हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हक्सर साहब ने कहा था कि पंचवर्षीय योजना के अगले दो वर्ष में दो सौ करोड़ रुपये का इस्तेमाल होगा। उस रुपये को हम बिजली और इन चीजों में इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन 25-28 वर्षों के बीच में हमने संविधान में घोषणा की है कि गरीबी-अमीरी की खाई पटेगी। हमने घोषणा की है कि समाजवादी समाज की रचना हमारा उद्देश्य है। हमने घोषणा की है कि अब तो हम भारत के संविधान में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्यूलर रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल करने जा रहे

[श्री कल्प नाथ राय]
हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान में, ब्रिटिश मोनोपली कैपिटल के बाद जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, तो यहां मोनोपली कैपिटल का विकास हुआ है या नहीं। आज हिन्दुस्तान की दौलत 50 बड़े बड़े मोनोपली हाउसेज के अन्दर है। हिन्दुस्तान के सौ पूंजीपतियों के हाथ में आज 50 प्रतिशत दौलत इकट्ठा हो गई है। चाहे बिड़ला साहब के कारखाने में पैदा होने वाली चीज हो, चाहे टाटा साहब के कारखाने में पैदा होने वाली चीज हो, या जयपुरिया के कारखाने में पैदा होने वाली चीज हो, उनके कारखानों में पैदा होने वाली चीजें, आज सोने के दाम में बाजार में बिक रही हैं और किसानों के खेत में पैदा होने वाली चीजें माटी के दाम में बिक रही हैं। आज हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था अच्छी हो गई है, यह बात सीना तानकर कही जाती है। इसका कारण यह है कि किसान ने अच्छी वर्षा होने के कारण 118 मिलियन टन अनाज पैदा किया है जिसके कारण संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का ढांचा बदल गया है। लेकिन अच्छी वर्षा का होना हमेशा मुनस्सर नहीं करता है। आज टेक्नालाजी गांवों में गई है, लेकिन वह कितनी मंहगी है। पूर्वांचल प्रदेश, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां पर 90 प्रतिशत किसान 1, 2 या 3 एकड़ खेत जोतते हैं। आज वहां से हजारों की संख्या में किसान गांवों को छोड़कर शहरों में भाग रहे हैं। इतनी भयानक परिस्थिति गांवों की है। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने तो हिन्दुस्तान के 7 लाख गांवों का ऐक्सप्लाय-टेशन केवल रा-मैटीरियल पैदा करने के लिए किया था। हिन्दुस्तान के 7 लाख गांवों में रा-मैटीरियल पैदा होगा और उसको मैनचेस्टर और इंग्लैंड के कारखानों में ले जाया जायेगा और उसी रा-मैटीरियलस से जो सामान बनेगा वह हिन्दुस्तान के बाजारों में मंहगे दामों पर बेचा जाएगा। यही कारण था कि हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आजादी की लड़ाई में किसानों का आह्वान किया और हिन्दुस्तान के किसानों ने अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से भगाया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किसानों ने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी। चाहे देश की आजादी की लड़ाई का सवाल हो, चाहे अनाज पैदा करने का सवाल हो, किसानों ने सर्वाधिक बलिदान किया। चाहे हिन्दुस्तान की सीमाओं की रक्षा का सवाल हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे चीन की सीमा हो, उन सीमाओं पर भारत की रक्षा के लिए किसानों के बच्चों का ही बलिदान हुआ। आज भी चाहे देश की सीमाओं की रक्षा का सवाल हो चाहे देश को अन्न देने का सवाल हो या देश की आजादी का सवाल हो, तो भी किसान ही सब कुछ देश के लिए न्यौछावर करेगा। लेकिन जब देश को लूटने का सवाल आयेगा तो लूटने का ठेका बिड़ला साहब, टाटा साहब या बड़े बड़े पूंजीपतियों का है। मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार से कि जो मोनोपली कैपिटल हिन्दुस्तान में पैदा हुआ है, यह जो रूरल सेक्टर की सम्पन्नता को खींचकर शहरों में लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है, इसको रोकने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। जब तक हम यहां एग्रिकल्चरल प्रोडूसेज के दाम निर्धारित हों जब तक हम यह नीति अख्तियार नहीं करेंगे तब तक हमारे देश के अन्दर कोई भी काम होने वाला नहीं है। आज गांवों में जितनी भी धन-दौलत पैदा होती है, इन्होंने मैकेनिज्म आफ ट्रेड, मैकेनिज्म आफ दि ऐक्सचेंज आफ कमोडिटीज, सर्कुलेशन और बाजार पर नियंत्रण की प्रक्रिया के मातहत सारे देश का पैसा इकट्ठा कर लिया है और ये लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। आज गांवों की स्थिति यह है कि वे उजड़ रहे हैं। इसलिए हिन्दुस्तान के अन्दर लगातार गरीबी-अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है और मोनोपली कैपिटल मैकेनिज्म आफ मार्केट, मैकेनिज्म आफ कमोडिटी ऐक्सचेंज, मैकेनिज्म आफ ट्रेड के द्वारा हिन्दुस्तान के

7 लाख गांवों का लगातार शोषण बढ़ता जा रहा है जिसके कारण मुट्ठी भर पूंजीपति तरक्की कर रहे हैं जिनके हाथों में अखबार है। बिड़ला साहब के हाथ में हिन्दुस्तान टाइम्स, टाटा साहब के हाथ में स्टेट्समैन और टाइम्स आफ इंडिया डालमिया ग्रुप के अन्तर्गत है। इनके हाथ में अखबार है, इनके हाथ में पोलिटिकल ताकत को इंफ्लुयेंस करने और अरबों, करोड़ों रुपये खर्च करने की ताकत है, हिन्दुस्तान के बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे मकान रखकर बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़े होटलों में पार्टी देने की ताकत है। इनकी ताकत लगातार देश में बढ़ती जा रही है और जो किसान हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की दौलत को बढ़ाया है, हिन्दुस्तान की सीमाओं की रक्षा में जिन्होंने अपने बेटों का बलिदान किया है व आज भी महान देश की महान नेता के कहने पर सब कुछ देश के लिये न्यौछावर करने के लिये तैयार हैं। हमारा कहना है हम पोलिटिकल स्टेबिलिटी लाए हैं। आज हिन्दुस्तान में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है तो वह है एकता की। लेकिन जब तक हम दाम बांधो की नीति अख्तियार नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। सरकार को यह नीति बनानी चाहिये कि जो वस्तु जितने दाम पर कारखानों में बनेगी उसके ड्योढ़े दाम पर वह वस्तु बिकेगी। यदि कोस्ट आफ प्रोडैक्शन कपड़े की चार आना गज है तो 6 आना गज के हिसाब से वह बिकेगा। जापान सरकार क्या करती है? जापान सरकार खुद सवा रुपये किलो के हिसाब से पूरा चावल खरीद लेती है और फिर उसे सवा रुपये से ज्यादा कीमत में बेचती है। वह किसान, जो एक रुपये का सामान सवा रुपये किलो के हिसाब से सरकार को देता है, पूरे साल एक रुपये के हिसाब से खरीदता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जापान में 17 परसेंट खेती करते हैं, अमेरिका में 3 परसेंट खेती करते हैं और इंगलैंड में 1 परसेंट खेती करते हैं लेकिन फिर भी वे लोग ज्यादा अन्न पैदा करने वाले हमारे जैसे मुल्क के किसानों से अधिक खुशहाल है। जापान सरकार ने एक कानून बनाया है कि जितने दाम पर बाजार के अंदर सामान बिकेगा उसका सवा दाम देकर सरकार किसानों से खरीद लेगी। जितने दाम पर बाजार में कोई वस्तु बिकती है उतने ही दाम पर, उन मिलों में काम करने वाले मजदूर, यदि सामान खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। आज हिन्दुस्तान के किसान तिहाई दाम पर खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश मे व्यापारी लोग किसानो से 80, 90 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदते हैं और सरकारी एजेंसियों को बेचते हैं। हम देखते हैं वही गेहूं बाजार मे 150 रुपये क्विंटल बिक रहा है। यहां पर उस किसान को सस्ते दाम पर अपना गेहूं बेचना पड़ता है। और जब खरीदने जाता है तो दुगुने दाम पर खरीदना पड़ता है। जो उसके अपने इस्तेमाल की चीजें हैं—चाहे वह कारखानों में बनने वाला कपड़ा हो, दवाएं हों या उसके बच्चों की किताबें हों—दुगुने दामो में मिलती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिग्री कालेजज और युनिवर्सिटियों की फीस ड्योढ़ी कर दी है। जो फीस पहले 18 रुपये थी अब वह 28 रुपये हो गई है। क्या हिन्दुस्तान का 18 एकड़ में खेत जोतने वाला किसान—मैं समझता हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ में खेत जोतने वाले मुश्किल से 5 परसेंट या 2 परसेंट व्यक्ति ही होंगे लेकिन 10 एकड़—5 एकड़ या दो एकड़ मे खेत जोतने वाले बहुत होंगे—क्या वह किसान अपने बेटों को युनिवर्सिटी या कालेज मे पढ़ा सकेगा? क्या 18 एकड़ में खेत जोतने वाला या उससे कम खेत जोतने वाला किसान एच० एम० टी० का ट्रैक्टर, जिसकी कीमत 25 हजार रुपये है और एक्साइज ड्यूटी लगा कर 50 हजार रुपये बैठती है, खरीद सकता है? मैं पूछना चाहता हू कि क्या वह किसान फर्टीलाइजर का इस्तेमाल कर सकता है, क्या वह किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकता है और क्या

[श्री कल्प नाथ राय]
वह किसान लेटैस्ट टैक्नोलोजी का उपयोग कर सकता है? आज किसान को अपने बीज लेने के लिये 105 रुपये क्विंटल के बदले 310 रुपये क्विंटल देने पड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि इस सवाल पर बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। प्लांनिग कमीशन को भी इस सवाल पर बैठ कर विचार करना चाहिये।

आज बिजली किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करता है। उसे 15 रुपये होर्स-पावर के हिसाब से बिजली मिलती है। यदि पूंजीपति, जैसे कि जयपुरिया साहब हैं, बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी 15 रुपये होर्सपावर के हिसाब से मिलेगी। 10 बीघा जमीन जोतने वाला किसान भी--चाहे वह 15 दिन ट्यूबवैल का इस्तेमाल करे या 12 महीने--उसे 15 रुपये होर्सपावर के हिसाब से बिजली के दाम देने पड़ेंगे। टाटा साहब हों या जयपुरिया साहब हों अगर वे 24 घंटे भी बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें भी 15 रुपये होर्सपावर के हिसाब से बिजली के दाम देने पड़ेंगे। यदि इंडस्ट्री कोई चलाये तो उसको सस्ते दाम पर बिजली दी जायेगी और यदि कोई खेती करेगा तो उसको महंगे दाम पर बिजली दी जायेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि 'दाम बांधों' नीति जब तक सरकार अख्तियार नहीं करेगी तब तक समता मूलक समाजवादी समाज की रचना नहीं हो सकती। हमारे आदरणीय इन्द्रदीप सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह ठीक ही रखा है कि जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिये, जैसे चीनी का उद्योग है, टैक्सटाइल का उद्योग है। उपसभापति जी, जब तक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण सरकार नहीं करेगी, जब तक सरकार उनको अपने हाथ में नहीं लेगी तब तक हिन्दुस्तान के किसानों को ठीक ढंग से चीजें नहीं मिल सकेंगी।

कांग्रेस पार्टी ने बम्बई अधिवेशन में यह प्रस्ताव किया था कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। लेकिन अभी तक चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। इसी का परिणाम यह है कि अभी पिछले दिनों चीनी मिल मालिकों की जो कांफ्रेंस हुई उसमें उनकी कारों की चमक-धमक बहुत दिखाई दी। बड़े बड़े पूंजीपति सरकार की राष्ट्रीयकरण न करने की नीति से खुश हैं क्योंकि उनको करोड़ों रुपयों का मुनाफा हो रहा है और आगामी नवम्बर के महीने में केन्द्रीय सरकार की जो नीति निर्धारित होगी उससे वे फायदा उठाने की साजिश चला रहे हैं। मैं भारत की प्रधान मंत्री और देश की महान् नेता श्रीमती इंदिरा गांधी से अपील करना चाहता हूं कि यदि फरवरी के महीने में कांग्रेस पार्टी चुनाव कराने जा रही है तो उससे पहले ही चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करना होगा और जिस चीज से हिन्दुस्तान की सरकार को 7 सौ करोड़ रुपये का फारन एक्सचेन्ज मिलता है उसके लिए किसानों को अच्छी कीमत देनी होगी, अच्छा दाम देना होगा। मैं समझता हूं कि अगर हमारे देश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाय तो 7 सौ करोड़ के बजाय हम 28 सौ करोड़ का फारन एक्सचेंज कमा सकते हैं और उस रुपये से हम अपने देश का औद्योगीकरण और उद्योगों का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार हम न केवल एशिया में बल्कि दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सकते हैं।

SHRIMATI HAMIDA HABIBULLAH (Uttar Pradesh) : Mr. Deputy Chairman, I thank you for giving me the opportunity to make my maiden speech before this august House.

While supporting the Resolution of Shri Indradeep Sinha, to a great extent, because it states the basic facts of life precisely and draws attention to the very fountain of our economic structure—that is to say, agricultural production and the remuneration therefrom—I actually feel that he could have made a stronger case, had he made constructive suggestions drawn from the very fine set of statistics and factual statements with which he regaled us, rather than spending time in giving us a long lecture on Marxism.

The hon. proposer's stress on the fact that in March, 1976 the prices of food articles had fallen by 15 per cent, with positively a startling recession in grains, cereals, pulses, vegetables and edible oil, in contrast to the rise in the prices of industrial goods and energy, power, light and lubricants, which rose in complete disproportion is a thing which must be faced squarely as a complete distortion of the whole economic pattern of our countryside.

Shri Sinha's vivid contrast on the one hand of costs of agriculture and cultivation inputs which had gone up by 48 per cent since 1971 pushing the cost of living of a peasant which had also gone up by 42 per cent and comparing it to a really marginal increase in the price of his produce, vividly highlights the predicament faced by the poor peasant.

While we welcome the increased cost of labour, it is obvious that this cost must be reflected in the wholesale prices. I am not aware of this having been done or having received enough attention. Everybody is more than aware of the fact that State Governments have increased land revenue, taxes, cost of electricity and water rates by double and even treble. They have even placed a high cess on commercial crops. We know well that inflation and deflation are primarily dependent on the cost of food materials.

Sir, we also know that any increase of the taxation burden, whether direct or indirect, reflects on the small farmer, because the ability of an individual to feed himself and his family is the primary need of an individual.

In a country where 75 per cent of the population is dependent on income directly or indirectly based on earnings derivable from agriculture, the cost of everything else is bound to stem from the agricultural income. If therefore the cost of ordinary consumer goods needed by the peasants produced by the industries of this country rises even by a few per cent while the costs of agricultural products go down, the cumulative and depressing effect over a large number of people of this country is bound to be disastrous. I will not deny that the state of the people in the rural areas is better today than it was thirty years ago. But the rise of the Indian capitalist out of all proportions to the improvement of the standard of the small peasant is a pointer to a dangerous situation—that is, accumulation of wealth in a few hands—and is, in fact, a denial of our hopes of social improvement and social justice.

Sir, it will be interesting to know what is meant by the honourable Member when he says that a remunerative price for agricultural produce should be fixed. With the

1 P.M.

size of holdings ranging from less than half an acre to 18 acres, what price is remunerative for whom? What is the standard of necessity for individuals within this spectrum? There is no doubt that over 50 per cent of the cultivators can scarcely produce enough to generate a surplus beyond their very minimum needs. They then have to sell to a middleman. It is these middlemen who, merely because they can manipulate and also generate enough finances, glean enormous profits, while the producer because of his inability to hold on to his produce because of acute need for money, is entirely at the mercy of these individuals. I am not referring to big farmers, because these are a dwindling species as the 20-point programme picks up momentum.

As things are, it is the middleman who controls the money. He depresses the prices at the time of harvest, lowering them to the minimum. He then raises the prices to fantastic heights when the market is entirely at his mercy. The example this year of the glut in groundnut and then the rise in the price of vanaspati to exorbitant proportions is typical of the manipulative power of the middleman.

Sir, at this stage of the discussion, the solution of the problems seems obvious, if the hon. Minister will take courage in both hands and face the complex problem squarely.

किसी का हौसला होता है तूफानों से लड़ने का।
सफीनों में तो सब दामने साहिल से गुजरते हैं।।

The solution of the problem of proper remuneration of all agricultural produce lies firstly in complete elimination of the middleman. Those who have made a good thing out of food products, cereals and other agricultural produce for centuries must now be prepared to be liquidated and take to other professions just as the zamindari class has had to alter its traditional livelihood methods.

Direct procurement and distribution systems are very necessary. The Food Corporation of India and other governmental systems have proved to be ineffective and inadequate, because they are an extension of bureaucracy, divorced from concern to help the people. In fact, the best solution possible is that there should be agro-centres established at every block which will supply fertilizer, grain and irrigation and cultivating equipment at such a cheap rate that it is sufficient to maintain these organisations at a little more than no-cost basis On no account should they be maximum profit-oriented. Some agencies which should consist of the local population, with the popular support of the local peasantry should be responsible for collection o

[Shrimati Mamida Habibullah]

every grain of surplus which the producers wish to sell. A price should be so fixed that the cost of modern cultivation is ensured leaving enough per acre of production for the peasant to be able to improve and maintain his technique.

Napoleon once said that "an army marches on its stomach". What we should realise is that a nation lives on its stomach. Therefore, it is important that by cutting out the middlemen, the nation should be not only the collector but the distributor of its own food. Societies and groups of producers drawn from the rural peasantry and their close city associates should be in charge of the distribution system through popular public agencies. If an army has to live on its stomach, is it not logical that the people of our country should not have to look over their shoulders for food but that the food should come forward to them wherever they are ? This should be the guiding principle of the distribution system.

Every mohalla and every village should have food easily supplied to them, food that has been collected through block, city and district centres. It should constitute both fresh rations and cereals which have been well stored in good store-houses and cold storages.

To summarise then, the means of production should be made available to every peasant at the cheapest and easiest rates. His produce should be collected and distributed by agencies of the people and not purely of officials.

The cost of electricity, water, fertilizer and seed should be kept at the minimum, as near as possible to the level of no profit and no loss. Only thus can we serve the people and fulfill the spirit of the 20-point programme.

Only yesterday our Prime Minister has again stated quite clearly that there must be a proper balance in the implementation of the 20-point programme. The imbalances in our rural economy have been mainly responsible for our imbalance between city and village leading to the poverty of the peasantry and the over-prosperity of the entrepreneurs.

Sir, I am quite confident that in the present atmosphere of hope and the co-operative mood of the people, if our competent and far-sighted Government could bring about a complete transformation not only in the agricultural pattern but in the cost of inputs, collection and distribution, with broad participation of the people and bring about a change from top to bottom in depth, then there is every indication that by changing the pattern of village economy, we can achieve our cherished goal of *garibi hatao*. Therefore, while supporting this Resolution, I would like to conclude by saying in all humility and with a note of courage :

"मुद्दत से जो सोचा करते थे अब वोह भी
जमाना आएगा
हर मुशकिल अब आसा होगी हर नक्शे
कोहन मिट जाएगा
अब कोई नया फ़ितना हरगिज़ तस्नीफ
न होने पाएगा ।"

Once again, I thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2.45 P.M.

The House then adjourned for lunch at six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at forty-seven minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman in the Chair.**

RESOLUTION RE. ENSURING REMUNERATIVE PRICES FOR AGRICULTURAL PRODUCE AND MAINTAINING PARITY IN PRICES BETWEEN AGRICULTURAL PRODUCE AND INDUSTRIAL GOODS—*Contd.*

श्री नत्थीसिह (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, सिह साहब ने जो यह प्रस्ताव रखा है वह सामयिक है । मैं समझता हूं शिन्दे साहब को अब तक इस सदन का और दूसरे सदन का मानस ज्ञात हो चुका है । इस सदन में इस प्रकार का प्रस्ताव पिछली बार भी आया था । तब भी एक स्वर से यह मांग की गयी थी कि हमारे देश का जो प्रमुख धन्धा है खेती उसको हम लाभ का धन्धा बनायें, आज जो वह एक अनइकानामिक प्रोफेशन के रूप में है उसमें न रहने दें । इस सदन में जो बात कही जाती है उस पर निश्चित रूप से ज्यादा ध्यान देने की आवयश्कता है । आज भी जब हम यह चर्चा करते है कि खेती के मूल्यों का लागत के साथ और मुनाफ के साथ सम्बन्ध होना चाहिए तो इस बात को गम्भीरता से नही लिया जाता । आज हम इस देश की तरक्की चाहते है, लोगों के रहन-सहन का स्तर बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा । खेती पर जो 80 प्रतिशत से ज्यादा